माटी से जुड़ाव और सांस्कृतिक निष्ठा ही सच्चा राष्ट्रबोध

जागरण संवाददाता, मंडी : राष्ट्र केवल सीमाओं, भौगोलिक नक्शों और सरकारी व्यवस्थाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह जनमानस की साझा संवेदना, सांस्कृतिक धरोहर और निस्स्वार्थ देशप्रेम की अखंड भावना का जीवंत स्वरूप है। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच जब राष्ट्रवाद की परिभाषाएं वैचारिक खांचों में बंटती जा रही हैं, तब साहित्य, कला और पत्रकारिता जैसे माध्यमों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये शब्द उपन्यासकार डा. गंगाराम राजी ने मंडी के होटल मेयफेयर में साहित्य, पत्रकारिता और राष्ट्रबोध विषय पर 'दैनिक जागरण' की विचार गोष्ठी में कहे।



मंडी के होटल मेयफेयर में साहित्य, पत्रकारिता और राष्ट्रबोध पर दैनिक जागरण की विचार गोष्ठी में भाग लेते साहित्कार व भाषा एवं संस्कृति अधिकारी● जागरण

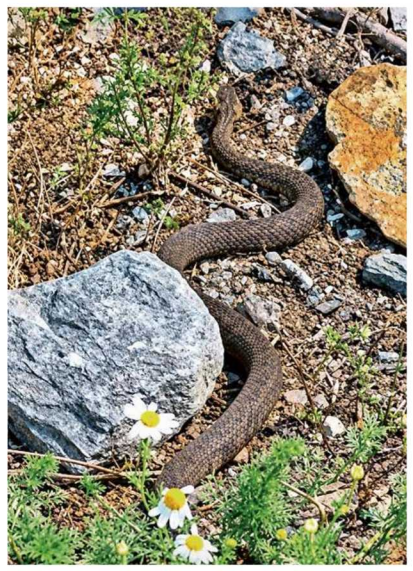
साहित्यकार डा. रेखा वशिष्ठ ने कहा कि इतिहास के पन्नों में जब हम राष्ट्र निर्माण के दौर को देखते हैं तो राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक विमर्श नहीं, बल्कि एक साझा भावनात्मक धागा था। आज की सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता पर दृष्टि डालें तो पहले सबका एक राष्ट्रवाद था, आज अपना-अपना वाली स्थिति है। राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग के आत्मसम्मान, कल्याण और सशक्तीकरण से जुड़ा है।

दैनिक जागरण विचार गोष्ठी

राष्ट्र केवल नक्शा नहीं, साझा संवेदना : डा. गंगाराम राजी

साहित्यकार डा. राकेश कपूर ने कहा कि किसी भी विशाल देश की पहचान उसकी स्थानीय बोलियों, परंपराओं और लोक-साहित्य के जीवंत रहने से होती है। जब तक नागरिक अपनी माटी और आंचलिक संस्कृति से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक व्यापक स्तर पर राष्ट्रबोध की संकल्पना अधूरी रहेगी। साहित्यकार, पत्रकार मुरारी शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत और उसकी सही पत्रकारिता एवं प्रस्तुति को बचाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। समृद्ध परंपराओं के प्रति निष्ठावान रहकर ही हम आधुनिक विकास की दौड़ में अपनी पहचान अक्षुण्ण रख सकते हैं।

जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति कोई थोपा हुआ विचार नहीं, बल्कि यह बचपन में मिलने वाले संस्कारों की उपज है। परिवारों में मातृशक्ति द्वारा दिए जाने वाले त्याग, सेवा और नैतिक मूल्य ही नई पीढ़ी को एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। साहित्यकार जगदीश कपूर ने कहा कि राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। प्रसिद्ध लोक गायिका एवं साहित्यकार कृष्णा ठाकुर ने कहा कि हमारी पारंपरिक लोकगाथाओं और लोकगीतों में देशभक्ति, त्याग और प्रकृति संरक्षण का संदेश गहराई से समाया है। गौरतलब है कि दैनिक जागरण द्वारा अपने पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन जी की स्मृति में आरंभ 11 लाख रुपये का साहित्य सम्मान गत वर्ष महेंद्र मधुकर की कृति 'वक्रतुंड' को दिया गया था जबकि इस वर्ष का सम्मान 10 अक्टूबर को दिल्ली में दिया जाएगा।


पांगी के छतवानी रिजर्व फारेस्ट में ट्रैप कैमरे में कैद हिमालयन पिट वाइपर ● सौ. विभाग

पांगी के जंगल में दिखा दुर्लभ हिमालयन पिट वाइपर

- पांगी के छतवानी रिजर्व फारेस्ट में लगाए ट्रैप कैमरा में हुआ कैद
- दुर्लभ प्रजाति का जहरीला सांप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता

जागरण संवाददाता, चंबा : चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल में हिमालयन पिट वाइपर की पहली बार तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पांगी के छतवानी रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र में हिमालयन पिट वाइपर दिखाई देने से स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ गई। यह सांप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला जहरीला सांप है। इसकी मौजूदगी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिमालयन पिट वाइपर का वैज्ञानिक नाम ग्लोइडियस हिमालयन है।

भारत में इस प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-दो के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन) की सूची में इसकी स्थिति कम चिंताजनक श्रेणी में दर्ज है। पांगी के छतवानी रिजर्व फारेस्ट में लगाया गया ट्रैप कैमरा वन्यजीवों की निगरानी के दौरान दुर्लभ हिमालयन पिट वाइपर की तस्वीर कैद करने में सफल रहा है। हिमालयन पिट वाइपर मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। पांगी घाटी जैसे दुर्गम और वन संपदा से समृद्ध क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी वन्यजीव विविधता के लिहाज से अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार पिट वाइपर प्रजाति के सांपों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।

वनमंडल अधिकारी पांगी रवि गुलेरिया ने बताया कि छतवानी रिजर्व फारेस्ट में हिमालयन पिट वाइपर का दिखाई देना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। लोगों से अपील है कि सांप दिखाई देने पर उससे दूरी बनाए रखें और उसे नुकसान न पहुंचाएं। सूचना वन विभाग को दें, ताकि सुरक्षित कार्रवाई की जा सके।

एक नजर में

स्पेशल एजुकेटर के 105 उम्मीदवार, तीन पद खाली

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 108 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड-25022 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने 105 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया है। पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग का एक पद खाली रह गया है, जबकि सामान्य अनारक्षित वर्ग के दो पद कोर्ट केस के चलते फिलहाल खाली रखे गए हैं। स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए 663 उम्मीदवारों में 643 ने परीक्षा दी। 290 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। (जासंके)

डीएलएड का पुनर्मूल्यांकन परिणाम हुआ घोषित

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून 2026 में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंटरी इन एजुकेशन भाग-एक एवं भाग-दो की परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डाक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षार्थी परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जून 2026 की डीएलएड परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण का अवसर प्रदान किया था। प्राप्त आवेदनों में डीएलएड भाग-एक के 30 व भाग-दो के आठ मामले सामने आए थे और अब इनका परिणाम घोषित किया है। (जासंके)

विशेष शिक्षक के 83 पदों का परिणाम घोषित

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विशेष शिक्षक कक्षा छह से 12वीं के 83 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती में 81 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। एससी डब्ल्यूएफएफ श्रेणी का एक पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गया है, जबकि एक पद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के चलते रिक्त रखा गया है। इन पदों के लिए कुल 271 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी आवेदकों को अस्थायी तौर पर पात्र मानते हुए परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया। 27 मई 2026 को कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें 260 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 11 अनुपस्थित रहे। (संस)

स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं नौ अक्टूबर से



जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीए, बीएससी और बीकाम प्रथम सेमेस्टर एनईपी-2020 की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ वार्षिक प्रणाली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की अनुपूरक प्रायोगिक परीक्षाएं नौ से 17 अक्टूबर तक होंगी।

विश्वविद्यालय की मूल्यांकन शाखा की ओर से सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भेजे पत्र में कहा है कि महाविद्यालय स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के समूह तैयार कर परीक्षा कार्यक्रम समय पर तय किया जाए। प्रायोगिक परीक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर वरिष्ठ एवं पात्र शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर उनकी जानकारी सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक उसी दिन महाविद्यालय अथवा संस्थान की ओर से अपलोड करने होंगे।

वीसी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय

हाई कोर्ट ने संशोधित कानून और फरवरी की भर्ती प्रक्रिया की थी खारिज

- प्रदेश सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में दी चुनौती
- दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 26 फरवरी 2026 को जारी कुलपति पद के विज्ञापन रद हो गए हैं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : कृषि व बागबानी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डा. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट के 27 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू नई चयन प्रक्रिया की रफ्तार पर भी अब कानूनी अनिश्चितता मंडरा रही है।

हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को प्रदेश सरकार द्वारा कुलपति नियुक्ति के लिए बदले कानूनी प्रविधानों और छह जनवरी 2026 को बनाए नियमों को भी असंवैधानिक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 2018 के विपरीत करार देते हुए निरस्त कर दिया था। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 26 फरवरी 2026 को जारी कुलपति पद के विज्ञापन भी इसी के साथ रद हो गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि कुलपति चयन में यूजीसी के अध्यक्ष के नामित सदस्य को शामिल करना जरूरी है।

अब पेच यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोक भवन स्तर पर दोनों विश्वविद्यालयों की पुरानी चयन समितियां हटाकर नए सिरे से प्रक्रिया की तैयारी शुरू की गई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद नई प्रक्रिया का भविष्य भी सर्वोच्च अदालत के रुख से जुड़ गया है। पहले 2025 में लोकभवन ने चयन प्रक्रिया शुरू की, फिर सरकार के बदले कानून के आधार पर फरवरी 2026 में अलग प्रक्रिया शुरू हुई।

हाई कोर्ट ने दूसरी प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि उसका आधार बने प्राविधानों को भी रद कर दिया।

कब क्या हुआ

- 15 मई 2025 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के लिए लोक भवन ने चयन समिति गठित की।
- 21 जून 2025 को नौणी के कुलपति चयन के लिए समिति गठित की गई।
- 21 जुलाई 2025 लोक भवन ने आवेदन आमंत्रित किए।
- छह जनवरी 2026 सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागबानी विश्वविद्यालय नियम, 2026 अधिसूचित किए। इन्हीं नियमों में सरकार को चयन समिति गठित करने और चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी।
- 26 फरवरी 2026 को कुलपति नियुक्ति के लिए नए विज्ञापन जारी किए गए।
- 27 मार्च 2026 फरवरी के विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख थी।
- 27 अगस्त 2026 को हिमाचल हाई कोर्ट ने संशोधित प्रविधान 2026 के नियम और 26 फरवरी के दोनों विज्ञापन निरस्त कर दिए।
- आठ सितंबर 2026 के हाई कोर्ट के फैसले के अनुपालन में पहले गठित दोनों चयन समिति को वापस करने की प्रक्रिया लोक भवन स्तर पर हुई और नई समितियों के गठन का रास्ता साफ किया गया।



विश्वविद्यालयों को सरकार देती है अनुदान : नरेश

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से चल रहा है और विश्वविद्यालयों को सरकार अनुदान देती है। ऐसे में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में नरेश चौहान ने कहा कि पहले भी सरकार के प्रस्ताव और राय के आधार पर कुलपतियों की नियुक्तियां होती रही हैं। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विचारधारा विशेष से जुड़े लोग शैक्षणिक संस्थानों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की भूमिका और राय को महत्व मिलना चाहिए।

पीएम सर को बताऊंगी चंबा के संघर्ष की कहानी : सीमा

केपी पांजला ● जागरण

- कहा- केंद्र की नीतियों के कारण ही इस मुकाम तक पहुंची
- विजेता खिलाड़ियों के साथ दिल्ली जाने को उत्साहित सीमा

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के गांव रेटा की धाविका सीमा कुमारी ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियन गेम्स की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में केंद्र सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीमा ने बताया कि एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और खिलाड़ी अपने-अपने घर लौट रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पदक विजेता अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी मिलने के लिए दिल्ली बुलाएंगे। सीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री चंबा जिला आ चुके हैं, और वह उन्हें चंबा की खूबसूरती और यहां के संघर्ष के बारे में बताना चाहती हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता केसरी देवी, जिलावासियों, एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया, साई और केंद्रीय खेल मंत्री को दिया। सीमा ने कहा कि इन सभी के समर्थन के कारण ही उनका हूनर गांव से निकलकर देश-विदेश में पहुंचा है। चंबा कालेज से स्नातक की पढ़ाई कर चुकी सीमा ने कहा कि देश ने उन्हें बहुत उत्साह दिया है। उनका मानना है कि खेलों में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक समर्थन और प्रेरणा का भी परिणाम है। सीमा की कहानी न केवल उनकी मेहनत और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सही नीतियों और समर्थन से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। वहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का भी डेढ़ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी काफी मदद की है।


सीमा कुमारी ● जागरण आर्काइव

हिमाचल की झोली में गुटखा व पान मसाला से आए 180 करोड़

- प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन ने केंद्र सरकार से मांगी थी हिमाचल की हिस्सेदारी
- पान मसाला व गुटखा खाने वालों से केंद्र की कमाई 4200 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : पान मसाला और गुटखा खाने वालों की जेब से निकला पैसा अब हिमाचल के खजाने तक पहुंचा है। केंद्र ने पान मसाला और गुटखा पर लगाए गए सेस से देशभर में करीब 4200 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। इसमें से हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपये मिले हैं। प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने केंद्र सरकार के समक्ष इस राशि में हिमाचल की हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव भेजा था।

ऐसे उत्पादों पर सेस लगाने के पीछे एक तरफ सरकार के लिए राजस्व जुटाना है तो दूसरी तरफ इनके सेवन को हतोत्साहित करना भी उद्देश्य है। तंबाकू और अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों का बोझ सीधे स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है।

ऐसे में इन उत्पादों से एकत्र राशि का हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में तंबाकू और गुटखा सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में 4200 करोड़ रुपये के केंद्रीय राजस्व में हिमाचल को मिली 180 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी आर्थिक के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुटखा और पान मसाला का सेवन मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है। इन उत्पादों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के पीछे लोगों को इनके सेवन से दूर करने का उद्देश्य भी जुड़ा है।



भारतीय स्टेट बैंक SBI

आपदग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, #40 एसडीए कॉम्प्लेक्स, आंचलिक कार्यालय भवन, कसुम्पटी, शिमला-171009 दूरभाष सं. 0177-2626796, 2626795, ई-मेल: sbi.18185@sbi.co.in

ईएमडी प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि: 26.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे
(बिक्री के समापन तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

निरीक्षण की तिथि एवं समयः 19.10.2026 को दोप. 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे

ई-नीलामी (ऑनलाईन नीलामी) के माध्यम से हाईपोथिकेटड परिसंपत्ति की बिक्री सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित चल संपत्ति, वाहन का पुनःकब्जा प्राप्त किया है और यह निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। ई-नीलामी का प्रबंध सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्रा. लि. द्वारा वेबसाईट https://baanknet.com/ के माध्यम से किया जाएगा।

क्रम. सं.	ऋणी/गारंटर का नाम एवं पता	परिसंपत्ति का विवरण	कुल देय राशि	आरक्षित कीमत (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में) / बोली वृद्धि राशि (रु. में)
1.	ऋणी:- श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शालिग राम, गांव बरोआ, पीओ ओहार, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर पिन.-174024	पंजीकरण सं. एचपी01बी 9393, पंजीकरण की तिथि: 19-मार्च-2020 विनिर्माण वर्ष: 01-2019, चैसिस सं. एमबीजेजेबीबीईएम701558066 इंजन सं. 2जीडीए275673, वाहन की श्रेणी: मोटर कैब (एलपीवी), ईंधन का प्रकार: डीजल, मेकर/मॉडल: टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.4जी, स्वामी का नाम: प्रदीप कुमार पुत्र शालिग राम।	रु. 15,91,956/- तथा उस पर उपार्जित एवं दण्डात्मक ब्याज से अलग + उस पर अन्य व्यय आदि (भौतिक कब्जे के अधीन)	रु. 7,60,000/- तथा जीएसटी @18% सहित	रु. 76,000/- / रु. 15,000/-

यह प्रकाशन उक्त ऋणियों एवं गारंटरों को पुनः कब्जे में लिए गए वाहन की बिक्री के लिए 15 दिनों की सूचना है

नियम एवं शर्तें: ई-नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता:- **मेसर्स पीएसबी एलायंस प्रा.लि.** की नीलामी वेबसाईट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑनलाईन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑनलाईन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों से युक्त ई-नीलामी निविदा दस्तावेज उपलब्ध है। इच्छुक बोलीदाता लोगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपनी ईएमडी (उक्त उल्लिखित अनुसार) वेबपोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें (यूजर आईडी एवं पासवर्ड नाम पंजीकरण द्वारा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है)। (बोलीदाता/क्रेता अपनी मोबाईल सं. एवं ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकृत हों। केवाईसी सत्यापन किया जाएगा, बोलीदाता को केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना वांछित है, जिनको **मेसर्स पीएसबी एलांयस प्रा.लि.** द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसमें 02 कार्यदिवस लग सकते है)। ईएमडी का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ई-नीलामी वेबसाईट पर **मेसर्स पीएसबी एलायंस प्रा.लि.** के साथ पंजीकृत बोलीदाता के अपने वॉलेट से की जाएगी। आगामी विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु, कृपया मेसर्स एमएसटीसी इकॉमर्स साईट पर पधारें। सिक्योर्ड क्रेडिटर को ज्ञात संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई संपत्ति के भार, शीर्षक, और दावों/अधिकारों/देयों/संपत्ति के प्रभावों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र तौर पर जांच करें। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता अथवा कोई प्रतिनिधित्व गठित नहीं करता है और न ही गठित करने से समझा जाए। संपत्ति सभी मौजूदा और आगामी भारों के साथ बेची जाएगी, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या न हो। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर मिसप्रिंटिंग त्रुटि अथवा किसी थर्ड पार्टी दावे/अधिकार/देय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बिक्री https://baanknet.com/ के अधीन निर्दिष्ट नियम/शर्तों का विषय होगी।

प्राधिकृत अधिकारी, मो. 82199-96108

दिनांक: 05.10.2026 स्थान: शिमला **प्राधिकृत अधिकारी**

पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा पैसा, सफाई कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : आर्थिक तंगी अब सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। शिक्षा विभाग ने नमस्ते योजना के तहत चिह्नित और सत्यापित सफाई कर्मचारियों के पात्र आश्रित विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित विद्यालयों को विद्यार्थियों का रिकार्ड सत्यापित कर आवेदन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से विद्यालयों को भेजी गई सूची में शामिल विद्यार्थियों के नाम, कक्षा, माता-पिता के नाम, आधार संख्या सहित अन्य विवरण स्कूल के अभिलेख से मिलाने होंगे। सत्यापन के बाद पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर योजना से जोड़कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी।

विद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया की कार्रवाई रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2026 तक शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यार्थी के आवेदन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सूची में शामिल कोई विद्यार्थी पात्र नहीं है या किसी कारण से उसका आवेदन नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण भी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा।

विभाग ने निजी विद्यालयों को भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। जिन विद्यालयों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल पंजीकरण करवाकर संस्थागत विवरण अद्यतन करना होगा। विभाग ने पूरी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

अब राज्य सचिवालय में नहीं होगा नेटवर्क का झंझट

1650 कर्मचारियों के लिए आर्म्सडेल फेज-1, फेज-2 और इलर्जली के दोनों भवनों में भी लगेगा वाई-फाई

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला: शिमला के छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। सचिवालय परिसर में अब फुल वाई-फाई सुविधा उपलब्ध होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय भवन, इलर्जली फेज-वन और टू में वाई-फाई राउटर और एक्सेस प्वाइंट लगाए जाएंगे। इससे फोन पर संपर्क और ई-आफिस को गति मिलेगी।

सचिवालय में लगभग 1650 अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। यहां की मोटी दीवारों और पहाड़ी लोकेशन के कारण मोबाइल फोन नेटवर्क कमजोर रहता है। ई-आफिस, वीडियो कान्फ्रेंसिंग और फाइल मूवमेंट के लिए तेज इंटरनेट की आवश्यकता है। जीएडी के एक अधिकारी ने बताया कि वाई-फाई की सुविधा से कर्मचारियों के फोन पर सीधा संपर्क संभव होगा और इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बेहतर होगी। इससे ई-फाइलों का निपटारा तेजी से होगा।

प्रदेश सचिवालय देश के उन चुनिंदा सचिवालयों में शामिल है, जहां अभी तक सेंट्रलाइज्ड वाई-फाई की सुविधा नहीं थी। केंद्र के कई विभागों में पहले से ही एनआइसी की मदद से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय: स्टार हाउस, एससीओ 76-82, सेक्टर 31-ए, चंडीगढ़-160030, दूरभाष 0172-2671517, 2671518, मो. 9464528861, 9468091053, ई-मेल: chandigarh.ard@bankofindia.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ऋणियों एवं गारंटरों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की अचल संपत्तियों के अचल संपत्तियों के लिए 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल/चल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/हाईपोथिकेटड/प्लेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल/चल संपत्तियों का सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया की निम्न वर्णित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संरचनात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी ऋणियों एवं गारंटरों से बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर के नियत संबंधित खाते के अंतर्गत निम्न वर्णित राशि की वसूली के लिए 12.11.2026 को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" एवं "जैसी भी है जो भी है"** आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित कीमत एवं जमा धरोहर राशि प्रत्येक खाते/संपत्तियों के अंतर्गत वर्णित की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेब पोर्टल BAANKNET: https://baanknet.com पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

शाखा का नाम / शेष राशि जमा खाता संख्या	खाता/ऋणी/गारंटर / मोर्टगेजर का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई-नीलामी की तिथि तिथि एवं समय
बी/ओ पांवटा साहिब दूरभाष: 01704-223594 (शेष राशि जमा खाता सं. 792490200000033, आईएफएससी कोड: बीकेआईडी0007924, खाते का नाम: डिसबर्समेंट)	(1) मेसर्स सुरजीत सिंह एण्ड सन्स, मकान सं. 173, वार्ड सं. 7, मेन बाजार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिप्र.-173205, (2) श्री सुरजीत सिंह पुत्र वीर सिंह, मकान सं. 173, वार्ड सं. 7, न्यू मेन बाजार, जिला सिरमौर, हिप्र.-173205, (3) श्री जसमीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, मकान सं. 173, वार्ड सं. 7, मेन बाजार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिप्र.	मौजा/मोहाल उपसंपदा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश माप प्लाट क्षेत्र 123.07 वर्ग मीटर में स्थित खाता खतौनी सं. 37/68, खसरा सं. 993, 994, 995, 996, 997 एवं 998, कित्ता 6, वार्ड सं. 7 में सम्मिलित भूमि एवं भवन की पंजीकृत मोर्टगेज, वर्ष 2022-23 के लिए जमाबंदी के अनुसार श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह द्वारा स्वामित्व। **संपत्ति की चौहद्दी:- पूर्वः** श्री विक्की की संपत्ति, **पश्चिमः** एमसी गली, **उत्तरः** खुला प्लाट, **दक्षिणः** श्री बलवंत सिंह का भवन।	रु. 2,05,25,706.83 जमा उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार / 23.04.2026 / 02.07.2026 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 1,79,00,000/- / र